'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2016
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.02.2016
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, वर्ल्ड प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 19 ● अंक 6 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 फरवरी, 2016

पंजाब केसरी में 3 फरवरी, 2016 को प्रकाशित लेख

दलित भेदभाव - राष्ट्र अवरोध

जातीय भेदभाव एवं लिंग विभाजन राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बनते? क्यों शोषित जाति ही अपने भेदभाव के खिलाफ खड़े हों, पूरा देश क्यों नहीं? क्या यह भेदभाव करने वाले दूसरे देश के हैं? लिंग भेद से कहीं बड़ा मुद्दा हमारे समाज में लिंग विभाजन का है, जिसको अभी तक पूरी मान्यता भी नहीं मिली है। रोहित वेमुला की आत्म-हत्या से देश में उबाल आ गया और जो विरोध कर रहे हैं, ज्यादातर दलित हैं और यह फिर से सिद्ध होता है कि वही अपनी लड़ाई लड़ें। यदि राष्ट्रीय मुद्दा यह बना होता तो क्या भारत हजारों वर्षों तक गुलाम हुआ होता? इस समय यह प्रश्न बर्बस दिमाग में उठ रहा है लेकिन यह लगभग असंभव है कि दलित भेदभाव राष्ट्रीय मुद्दा बने।

रोहित वेमुला की घटना के बाद हजारों भेदभाव के मामले उभर गए हैं। यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी भेदभाव बड़े पैमाने पर दिखने लगा। दिल्ली विश्वविद्यालय हो या आई.आई.टी. या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेदभाव होना आम दिनचर्या है। अपवाद को छोड़कर शायद ही कोई मिलता है, जो जातीय उत्पीड़न न करे। ऐसे उत्पीड़न होते हैं, जिसका संबंध दूर-दराज तक तथ्यों से भी नहीं होता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग कॉलेज की शिक्षिका - शशि मावर का उत्पीड़न किया गया कि उन्होंने छात्रों के साथ अच्छा वर्ताव नहीं किया। उन्होंने उत्पीड़न का बयान करते हुए कहा कि जिस कक्षा के बच्चों को वे पढ़ाती ही नहीं, उनके बारे में इन पर भेदभाव का आरोप प्रशासन ने मढ़ा। प्रायः जो छात्र शोध करते हैं, यह कहते हैं कि उनके गाइड उन पर उत्पीड़न करते हैं। महिला हों तो शारीरिक शोषण का प्रयास होता है। अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार की एक दलित शिक्षिका के साथ ऐसा भेदभाव हुआ कि जो लोगों की सोच के परे है। जब वे कक्षा में पढ़ाती हैं तो डीन आकर बैठ जाते हैं। ऐसे में जिन विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, वे क्या सम्मान देंगे और इस दलित शिक्षिका के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी ग्रहण करने में गंभीरता नहीं होगी। मान लिया जाए कि दलित शिक्षिका के पढ़ाने के तौर-तरीके ठीक नहीं थे तो अलग से समझाना चाहिए था या पढ़ाए गए छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन। कुल मिलाकर भेदभाव करने का मौका मिलना चाहिए। ये भेदभाव करने वाले क्या ईसाई, यहूदी, पारसी, चीनी, अमरीकी, मुस्लिम हैं? राजनीति में इस अहम् सवाल को कभी संबोधित नहीं किया गया। जो आरोप मार्क्सवादियों पर लगता है कि उन्होंने विदेशी मॉडल को ज्यों का त्यों भारत के परिप्रेक्ष्य में लागू किया, लगभग वही आरोप हम सब पर लगना चाहिए। जनतंत्र को हमने स्वीकार तो किया, जिसका आविर्भाव व विकास यूरोपीय देशों में हुआ था लेकिन राज्य के कल्याणकारी चरित्र के बाहर नहीं जा सके। जिस समाज में जातिवाद नहीं था, वहां तो राज्य का चरित्र कल्याणकारी होना ही है, लेकिन हमारे समाज भिन्न है। इसलिए इसके जाति-व्यवस्था के प्रश्न को राज्य को संबोधित करना चाहिए था।

रोहित वेमुला से भी दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, परन्तु जितना मीडिया में कवरेज इसको मिला किसी और घटना को नहीं। गुस्सा, दर्द और आक्रोश जो दबे हुए थे, वे इस घटना के माध्यम से प्रकट हुए। निर्भया की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे जघन्य अपराध पहले न होते रहे हों। महिलाओं पर हो रहे भेदभाव, उत्पीड़न आदि पर जो गुस्सा और दर्द दबा हुआ था वह उस समय प्रकट हो गया था। मीडिया की बड़ी भूमिका रोहित वेमुला की घटना को राष्ट्रव्यापी बनाने में रही। यह भी समय और परिस्थिति की ही देन थी कि मीडिया ने इतनी हवा इस घटना को दे दी। क्या इससे हम मानें कि मीडिया का रिश्ता दर्द का है। जितना मीडिया भेदभाव करती है, उतना कोई और कर ही नहीं सकता। किसी भी राष्ट्रीय अखबार में दलित के बारे में खबर तभी छपती है जब कोई घटना हो। इनके सशक्तिकरण और समस्या पर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो खबर को स्थान देकर इनका भला कर सकती थी। 365 दिन के अखबार उठाकर देख लिए जाएं तो दलित के द्वारा लिखा गया लेख पढ़ने को नहीं मिलेगा। रोहित वेमुला पर मैं लिखना चाहा और अखबारों से सम्पर्क किया तो लगभग सभी ने मना कर दिया लेख लेने से। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखवा भी लिया यह कहते हुए कि इस पर उनके पास कोई लेख नहीं है, तो मैंने भेज दिया। लेख को वापिस लौटा दिया गया। इसी विषय पर इंडियन एक्सप्रेस ने मेरे विचार संपादकीय पृष्ठ पर छापे जिसकी देश-विदेश से बड़ी अच्छी टिप्पणियां आईं। इतने भी हम गए गुजरे नहीं हैं कि हम लिख नहीं सकते।

मीडिया सबसे ज्यादा जातिवादी है। यह तथ्यों के आधार पर कहा जा रहा है। इंडिया टुडे, आईबीएन 7, इंडिया टीवी, हिन्दुस्तान टाइम्स जैसे तमाम अखबार और चैनल वार्षिक सम्मेलन करते हैं, जिसमें देश-विदेश से अतिथि और वक्ता बुलाए जाते हैं, जिसमें दलित को आमंत्रित नहीं किया जाता। भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जिन क्षेत्रों में दलितों और पिछड़ों की पारंगता अर्थात् उपलब्धि खास न हो उन्हीं पर चर्चा और पुरस्कार आयोजित होते हैं, ताकि इन्हें बाहर रखा जा सके। चूंकि भारतीय समाज पेशा पर आधारित रहा है, इसलिए दलित-पिछड़े उन्हीं क्षेत्रों में माहिर हो सकते हैं, जो सदियों से करते आ रहे हैं। सोसल मीडिया पर

तमाम टिप्पणियां कई सालों से उस समय भरमार हो जाती हैं जब 26 जनवरी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, घोषित होता है। चूंकि दलित-पिछड़े को नहीं मिलता है, इसलिए उस समय गुस्सा फूटता है। सारे इंजीनियरिंग आदि विषय दूसरे देशों में क्यों विकसित हुए? वहां पर इसलिए विकसित हुए कि जो हाथ चमड़ा, बर्तन, लोहा, कपड़ा आदि में सने, उनको सम्मान दिया गया और इन्हीं विषयों पर वे शोध कर सके और अंततः ज्ञान का भंडार अर्थात् विषय बनते गए। हमारे यहां इन हाथों को नीच और अछूत कहा गया।

तथाकथित राष्ट्रभक्तों से कुछ कहना है कि रोहित वेमुला जैसी घटना से राष्ट्र को जितनी हानि होती है, उतनी शायद किसी से नहीं। इतनी बड़ी आबादी को दबाकर और अलग करके क्या किसी देश को विकसित और खुशहाल बनाया जा सकता है? दलित अपनी मुक्ति की लड़ाई वही क्यों लड़ें? बल्कि राष्ट्र भक्ति का भाषण देने वालों को ज्यादा लड़ना चाहिए। दलित-पिछड़े हजारों वर्षों से अभाव की जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं तो आगे भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या हमारा देश रेस में उन देशों के साथ भाग सकता है जो विकसित हो गए हों या उस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हों। यह गारंटी है कि इतनी बड़ी आबादी को काटकर देश को विकसित नहीं बनाया जा सकता है। अतीत से हमने कुछ सीखा नहीं है। सिकंदर 327 बीसी में भारत पर हमला करता है और जीत आसानी से हासिल किया और उसके बाद से हमले दर हमले होते रहे और हम परास्त। यह नहीं कि हमारी बाजुओं में दम नहीं था या बुद्धि की कमी थी। कारण यह था कि हम जातियों में बंटे थे। अंग्रेजों ने तो हमें दो भागों में बांटा लेकिन हमने तो जाति के आधार पर हजारों टुकड़ों में बांट दिया। जो राष्ट्रभक्त होने का दंभ भरते हैं, उन्हें दलितों से भी आगे आकर रोहित वेमुला जैसे मामले को उठना चाहिए लेकिन करते हैं दिखावा, क्योंकि लेना है वोट और प्राप्त करना है स्वयं की प्रसिद्धि, ज्ञान और धर्मादा के क्षेत्र में प्रभुत्व।

- डॉ0 उदित राज

पदाधिकारियों, शुभचिंतकों व समर्थकों के मो. नं भेजें

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के पदाधिकारियों से आग्रह है कि वे अधिक से अधिक संख्या में साथियों के मोबाइल नं. भेजें। ये मोबाइल नं. दो श्रेणियों में विभाजित करके भेजें। श्रेणी-A में परिसंघ के नेताओं और महत्त्वपूर्ण लोगों के नंबर होने चाहिए और श्रेणी-B में अन्य सामाजिक लोगों और सहयोगियों के नंबर होने चाहिए। इन्हें नीचे लिखे प्रारूप में parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

- डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

परिसंघ की सदस्यता का विवरण भेजें

बार-बार आग्रह करने के बाद भी अभी तक अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की जो सदस्यता की रसीदें जारी की गयी थी, वापिस नहीं आ सकी हैं। परिसंघ के प्रदेश, जिला, ब्लाक इकाइयों के पदाधिकारियों व शुभचिंतकों, जिनके पास सदस्यता की रसीदें हैं, वे नाम, मोबाइल नं., जिला एवं प्रदेश लिखकर नीचे लिखे प्रारूप में अतिशीघ्र parisangh1997@gmail.com पर ईमेल करें।

सदस्य का नाम	मोबाइल नं.	जिला	प्रदेश

- डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष

ग़नीमत है कि वे केवल आरक्षण मांग रहे हैं...

यदि आपको किसी रोज़ अचानक पता चले कि आप जिस घर में रहते हैं, वह घर किसी और का था और आपके पिता ने छल करके वह अपने नाम लिखवाया है तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आपके पिता ने छला था, उसका क़त्ल भी आपके पिता ने ही करवाया था? और कैसा लगेगा यह जानकर कि जिस व्यक्ति का क़त्ल आपके पिता ने किया था, क़त्ल वाली रात उसकी पत्नी की इज्ज़त भी आपके बाप ने लूटी थी और उस महिला ने बाद में आत्महत्या कर ली थी? और कैसा लगेगा अगर उस मारे गए दंपत्ति का बेटा एक दिन आपके सामने आ जाए और बोले, 'मुझे मेरा घर वापस दो, मुझे मेरी माता के अपमान और पिता की हत्या का मुआवज़ा दो।

आप क्या करेंगे और आप क्या कहेंगे, यह निर्भर करता है इस बात पर कि आप कैसे व्यक्ति हैं। यदि आप अपने बाप की ही तरह के होंगे तो आप उसे अपने नौकरों के हाथों पिटवा देंगे और मां-बहन की गाली देकर कहेंगे, 'क्या बकवास करता है? यह घर मेरा है और मेरे पिता ने अपनी मेहनत से कमाया है। अपनी गंदी मां का नाम मेरे शरीफ़ पिता के साथ जोड़कर तू उनको बदनाम करना चाहता है! साले, तू जानता नहीं, मैं कौन हूं। फिर कभी ऐसी गंदी बात कही ना मेरे पिता के बारे में तो सीधे जेल भिजवा दूंगा। सारी उमर चक्की पीसता रहेगा।' यह कहकर आप अपने आलीशान ड्रॉइंग रूम में चले जाएंगे मन में बड़बड़ाते हुए, 'कुत्ता साला, पूरा मूड ख़राब कर दिया सुबह-सुबह।'

और अगर आप सेंसिटिव होंगे, आपके भीतर इंसानियत होगी, आप न्याय-अन्याय में विश्वास करते होंगे तो आप उस लड़के से बात करेंगे, सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और जब सच पता चलेगा कि आपके पिता वाक़ई वैसे ही थे तो आपको अपने पिता से घृणा हो जाएगी, घर की एक-एक ईंट से आपको ख़ून टपकता दिखाई देगा। वहां आपको लड़के के मृत माता-पिता की आत्माएं घूमती नज़र आएंगी। आप उस घर में एक पल भी नहीं रह पाएंगे। आप उस लड़के से माफ़ी मांगेंगे और कहेंगे, 'मैं अपने पिता के पापों को अनहुआ तो नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे माता-पिता को जीवित भी नहीं कर सकता। मगर यह घर जो तुम्हारा है, मैं तुमको सौंपता हूं।' यह कहकर आप निकल जाएंगे।

सोच में पड़ गए आप? आप सोच रहे होंगे कि आपके पिता तो ऐसे हैं ही नहीं इसलिए आपके सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। चलिए, पिता को छोड़ देते हैं। वे शायद ऐसे न हों (हालांकि क्या गारंटी है)। लेकिन आपके दादा या परदादा या उससे भी पहले के पूर्वज - वे कैसे थे? कभी जानने का प्रयास किया है, आपके बाप-दादों और पूर्वजों ने क्या-क्या कुकर्म किए हैं।

शूद्रों को आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता।

<u>शूद्रों को आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता।</u>

आपके पूर्वजों ने समाज के एक वर्ग को सदियों तक शिक्षा-दीक्षा से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा, उनको बस्ती से बाहर नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया, उनकी छाया से दूर रहे लेकिन उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया, और प्रतिरोध करने पर उनको लठैतों से पिटवा दिया, उनकी झोपड़ियां जला दीं। और यह सब करते हुए उन्होंने ज़मीनें क़ब्ज़ाईं, हवामहल बनाए, पत्नियों के लिए गहने गढ़वाए और अय्याशी की। अपने उन आततायी पूर्वजों की उस पाप की कमाई के बल पर ही आप आज उस जगह पर है जहां आप हैं। अच्छा पक्का घर है, गांव में ज़मीन है, पढ़ाई भी अच्छे स्कूल या कॉलेज से की है, और प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं या घर का व्यवसाय है।

सोचिए, यदि आप उस दूसरे वर्ग में पैदा हुए होते तो आप आज कहां होते? वहां होते, जहां हैं? नहीं होते। ज्यादा सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अपने ऑफ़िस में काम करने वाले लोगों के सरनेम याद कर लीजिए। बॉस से लेकर चपरासी तक - 70 से 80 परसेंट तक - सब ऊंची जाति के होंगे। कितने हैं उनमें जो दलित हैं? यदि आप गांव में रहते हैं तो एक बार गांव का मुआयना कर लीजिए और सवर्णों और दलितों के इलाक़ों की तुलना करके देख लीजिए।

यदि उन दलितों का हाल थोड़ा भी अच्छा है तो वह इसलिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित करते हुए यह फ़ैसला किया कि शिक्षा में और नौकरियों में दलितों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। यह भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की ताकि सवर्ण अपने रुसूख़, दौलत और ताक़त के बल पर सारी सुविधाएं ख़ुद ही बटोर न ले जाएं।

एकलव्य की कथा जातीय अन्याय की कहानी है लेकिन इसे गुरुभक्ति के उदाहरण के तौर पर प्रचारित किया जाता है।

आश्चर्य होता है जब ऐसे लोग जिनके पूर्वजों के पाप मैंने ऊपर गिनवाए, दलितों से कहते हैं कि आरक्षण की भीख मांगना बंद करो। यह बात वे कह रहे हैं जिनके बाप-दादों ने शिक्षा और संपत्ति पर पिछले दो हज़ार सालों या उससे भी ज्यादा समय से 100 परसेंट आरक्षण अपने समुदाय के नाम कर रखा है। आदिवासी एकलव्य धनुर्विद्या नहीं सीख सकता था। सीख ली तो उसे अंगूठा कटवाना पड़ा ताकि वह एक राजपुत्र अर्जुन से श्रेष्ठ न निकल जाए। शूद्र शंबूक तपस्या नहीं कर सकता था और इस अपराध के लिए राम ने ब्राह्मणों की शिकायत पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कितना अद्भुत न्याय है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। और मनु महाराज के क्या कहने। उनका कानून है कि यदि किसी शूद्र के कान में वेदमंत्र चले गए तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए। और कैसी महान हिंदू संस्कृति है कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। प्रवेश करेंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे।

<u>शंबूक की हत्या रामायण का एक अत्यंत घृणित अध्याय है मगर इसे कभी भी सामने नहीं लाया जाता।</u>

शंबूक की हत्या रामायण का एक अत्यंत घृणित अध्याय है मगर इसे कभी भी सामने नहीं लाया जाता। आदिकाल से चला आ रहा है यह अन्याय और आज भी चल रहा है। आदिकाल से एक समूह को पढ़ने-लिखने-सीखने और आगे बढ़ने से वंचित रखा गया, समाज से काटकर अलग रखा गया, उसे अपमानित किया गया। इसी कारण आज वे इस स्थिति में नहीं हैं कि आपसे मुकाबला कर सकें। इसीलिए उनको आरक्षण चाहिए। किसी को सालों तक अंधेरे कमरे में बांधकर रखो, खाने-पीने को कुछ न दो और फिर एक दिन बंधन खोलकर कहो कि आओ, मेरे साथ दौड़ो। मेरी बराबरी करो। यह न्याय है या मज़ाक़ है?

और एक बात। कहा जा रहा है कि जातिवाद का फ़ायदा उठाना छोड़ो और हमारे साथ जाति तोड़ने की मुहीम में शामिल हो जाओ। कमाल है। जातीय श्रेष्ठता का बिगुल बजाने वाले आज जाति तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आज उनको जाति के कारण परेशानी आ रही है। जब तक जाति के नाम पर अपना वर्चस्व चल रहा था, तब तक जाति बहुत अच्छी थी। आज भी दोस्ती-यारी और खाने-पीने से लेकर शादी-ब्याह तक में ये जाति के दायरे से बाहर नहीं निकलते लेकिन आरक्षण के कारण कॉलेजों में सीटें कम हो गईं, सरकारी नौकरियां कम हो गईं तो नारा दे रहे हैं जाति तोड़ने का। उत्कर्ष और उनके भाइयो, जाति तोड़नी है तो पहले अपने बाप और दादा-दादी से जाकर कह दो कि 'मैं दहेज लेकर आपके द्वारा चुनी गई अपनी ही जाति की लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं ख़ुद चुनूंगा अपनी जीवन-संगिनी। अपनी पसंद से करूंगा चाहे वह जिस जाति या धर्म की हो।' ऐसा कहो, फिर उस पर अमल करो और अपनी उस विजातीय या विधर्मी पत्नी को लेकर अपने बाप-दादा के घर जाओ। यदि घरवाले उसे स्वीकार न करें तो अपना घर-परिवार छोड़ दो।

जिस दिन तुम यह सब करोगे, उस दिन तुम्हारे सर से तुम्हारे पूर्वजों के पाप का बोझ ख़त्म होगा। वरना तुम्हारी हर सांस उन दलितों और वंचितों की ऋणी है। ख़ैर मनाओ कि वे अपने हिस्से की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियां ही मांग रहे हैं। अगर उनके और उनके पूर्वजों के ख़ून, पसीने और आंसुओं का हिसाब करने बैठेंगे तो तुम्हारे रक्त की एक-एक बूंद, तुम्हारे घर की एक-एक ईंट और तुम्हारे बैंक में पड़ा एक-एक रुपया उनके हिस्से में चला जाएगा।

.....

http://blogs.navbharattimes.indiatimes.com/ekla-chalo/the-sins-of-upper-castes-down-the-ages-justify-reservations/?utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=BlogReservation080216

+++

खुला ख़त- न्यूयार्क में दलित और दिल्ली में ब्राह्मण बनकर रहने वाली महिला पत्रकार के नाम

बी.बी.सी. ज़रिए तुम्हारी कहानी सारा देश और दुनिया पढ़ रही है। तुम अब न्यूयार्क में हो और भारतीय जाति व्यवस्था को लेकर तुम्हारे बेहद कड़वे अनुभव हैं। इसीलिए तुमने अब तक अपनी दलित पहचान को छिपाया।

तुम्हें यह जानकर ख़ुशी होगी कि अब भारत में बहुजन लोगों ने अपनी पहचान से डरना बंद कर दिया है। हर कैंपस में फुले, बिरसा और आंबेडकर के नाम पर छात्र संगठन और प्रोफेसरों के संगठन चल रहे हैं। जाति को एक समस्या के तौर पर स्वीकार करना, जाति मुक्ति की दिशा में पहला कदम है। पंजाब में तो एक करोड़ की कार के पीछे लोग वठ से संत रविदास की पन्नेटे लगा रहे हैं।

तुमने जाति छिपाई, इससे समस्या कहां ख़त्म हुई। ये टी.बी. के समय होने वाले बुख़ार के समय क्रेसिन लेने वाली बात है। तुम्हारा जाति छिपाना एक निजी फ़ैसला था, जिससे देश और समाज को कुछ नहीं मिला। आज लोग तुम्हें इसलिये जान रहे हैं कि तुम अपनी पहचान के साथ सबके बीच हो। वरना, पहचान छिपाए लोग कब मर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। उनके लिए सिर्फ परिवार रोता है। वहीं देखो, रोहित वेमुला के साथ देश रो रहा है। रोहित वेमुला की फुले, आंबेडकरी पहचान है। वह कमजोरी नहीं, ताकत है।

फिर छुपाना क्यों? तुम इस देश की सबसे मेहनतकश बिरादरी से हो। तुम्हारे पुरखों ने यह देश बनाया है। तुम मालकिन हो। शर्म से मुंह छिपाएं निठल्ले लोग। तुम बुद्ध, कबीर, रैदास, फुले, सावित्रीबाई, बाबा साहेब की परंपरा की संतान हो। जिस परंपरा ने देश को सबसे बड़े विद्वान दिए। उम्मीद है कि तुम यह समझ पा रही हो।

<u>दिलीप सी मंडल की फेसबुक वाल से</u>

http://www.kohraam.com/my-opinion/open-letter-to-yashika-datt-from-dilip-c-mandal-50045.html

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 19 ● Issue 6 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 February, 2016

Is it a mother's love?

A saddest incident happened on 17th January at the University of Hyderabad. Rohith Vemula committed suicide leaving a letter behind saying that his life was hollow. He had been alienated from himself from childhood, and felt solitary all throughout and reduced to a mere object. He was one amongst five students who were initially expelled from the University, which was later modified to suspension from hostel. The incident spread all over the country like wildfire. All range of forces is attacking left and right on Shri Bandaru Dattatreya, Minister of State of Labor and Employment, and Smt. Smriti Irani, HRD Minister and the University administration for their letter blaming students for anti-national activities. Here I am not passing any value judgment; therefore there is no question of exonerating anyone being accused. This has unfolded an opportunity to examine those who are lamenting, crying, protesting – do they really harbor a mother's love? Can there be a substitute of nurses' love without performing that?

It has become the order of the day that Dalit children at many schools eat midday meals separately. There are separate hostels for Dalit students; scholarships are denied and when delivered, it is too late and they are not allowed to appear in examinations. Hostels are in dilapidated condition. Often, students in engineering and medical colleges are discriminated against in internal assessment. To do justice to SC/ST examinees for different Govt. services, separate interview Board is created for their interview so that they can secure average marks of that of General category. Despite this protection, the average marks in interview are much lower; students belonging to SC/ST doing Ph.D. or research are often discriminated. It is not an isolated incident that reserved seats are unfilled since Govt. policies to outsource work, downsize the department, CRS and VRS have diluted reservation to a great extent. Lacs of posts are lying vacant due to Courts' interference; denial of reservation in promotion has created hurdles. In Uttar Pradesh, thousands of SC/ST officers and employees have been demoted so much so that those who have competed in General merit have been also demoted. The All India Confederation of SC/ST Organizations, which I represent as its National Chairman, has been fighting for these rights.

If the fruits of reservation in politics, Government jobs and education would have not come to them, majority of SC/STs would have been living a primitive life. Rohith Vemula is also a directly or indirectly a product of reservation; if reservation was not there, he would have not reached the University, its hostel, suspension and suicide. What SC/STs could not achieve in thousands of years, they could get in less than 70 years ever since reservation was introduced. Some say that reservation has benefited a few, may I ask them which other fields included SC/STs, be it media, trade, markets, industry, import and export, share markets, arts and culture, higher education and judiciary? Upliftment and empowerment, other than through reservation, is also due to its impact. Before reservation was introduced, why there was no participation at all by these people in any field?

The Leftist forces are in the forefront to condemn the Government – may I ask them that when we fight for our main source of empowerment and participation, where are they? Except sometime, they issue statements in our favor, but at the helm of affairs, it's the SCs and STs who fight or political parties are galvanized to accede to the demands due to vote pressures. When Rohith Vemula was on strike for 15 days, where were these people? The CPM student wing, SFI opposed Rohith. The All India Confederation of SC/ST Organizations came into existence in 1997 to get the 5 anti-reservation orders issued in 1997 cancelled. It is notable that these orders were issued when the Social Justice Government was in power. When we started struggling year after year from the streets to Ramlila Maidan and Jantar Mantar, these Leftists were never seen. It was the Vajpayee Govt. which cancelled the 5 anti-reservation orders. Do they ever take out consistent rallies, demonstrations, dharnas for our rights, which are a life and death question for us? For them, reality is poor and rich, and thus they sweep caste discrimination under the carpet. Can they prove that their approach has empowered SC/STs? If so, then there would have been number of political, social and business leaders amongst SC/STs in Bengal, Tripura and Kerala.

When we are killed, beaten, humiliated, discriminated, sometimes forces ranging from media to centre and right cry hoarse, as if it is really mother's care. When we fight for our dignity, empowerment and participation, not even single line is published or shown. Rohith Vemula participated in the rally of 7th Dec at Ramlila Ground Delhi conducted under the aegis of All India Confederation of SC/ST Organizations, which was to prese for reservation in promotion and private sector – where was the media and these people? He knew what would empower him.. It filled Ramlila Ground, and yet it could not become news; this has been happening since beginning. Denial of reservation rights kills millions of Rohith Vemulas, is it possible to save life and dignity without rights? Sometimes, they mourn our death, and condemn discrimination, but do they ever fight for strengthening the root which can empower, give dignity and inclusion? Some Dalits are even attacking me that I have surrendered to the BJP, and not coming out to condemn - no allurement can change me and I know what I have to do. I ask them also that why don't they work together under the leadership of Dalits? Rather, more follow upper caste leadership - they practice casteism amongst themselves. So long as caste divisions persist, any attempt to develop nation will be a mirage.

+++

'Dalits face Rohith's ordeals daily... Pity we have no Lincoln'

DECCAN CHRONICLE. | MANISH ANAND
Published on Jan 31, 2016,

'It's a misfortune that in India there's no one like Abraham Lincoln, who advocated rights for blacks.

What do you have to say about Rohith Vemula's suicide?

It is a very unfortunate incident. But let me tell you, it's the order of the day. The only difference is that the Vemula incident has got national attention. But the ordeals faced by Vemula are experienced by dalit students every day in schools and colleges. Upper-caste students do not even eat meals with dalits. Dalits face discrimination in all forms.

How do you see the agitation following Vemula's suicide and the subsequent political interest in the case?

Whenever such incidents take place, the so-called "learned" people cry and make noise. But why they did not raise the issue before? Now they are coming forward to champion the dalit cause, but where were they when teaching vacancies were not filled up? When hostels remained in dilapidated conditions? When scholarships were not given? When the University Grants Commission did not spend the money (2012-13) meant for Scheduled Castes or Scheduled Tribes?

Dr. Udit Raj, Bharatiya Janata Party MP and dalit leader, firm in his belief that untouchability against dalits is all-pervasive, says that Rohith Vemula's suicide could have been prevented if some positive action had been taken. In an interview with Manish Anand. Dr Raj runs the fact that India will never see an Abraham Lincoln as even the likes of Mahatma Gandhi and Swami Vivekananda advocated eradication of caste evils but not the caste system.

If they were consistent in championing the cause of dalits, Vemula would not have committed suicide. We face untouchability everywhere. Even the media is not an exception. Many media conclaves are held each year. Have you ever seen any dalit speaker in attendance? You see Muslim representatives, but out of 30 crore dalits, not even one dalit speaker is invited.

There has been criticism about the manner in which the National Democratic Alliance government and the BJP reacted to the incident. Further, the BJP is facing much flak for minister of state for external affairs Gen. V.K. Singh's statement on dalits (on the murder of two dalit children in Faridabad in 2015).

The BJP did not subscribe to the statement of Gen. Singh and he tendered

(Contd. on page 6)

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax: 23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisagh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya

This Is How One Woman's Rebellion Abolished Kerala's Oppressive 'Breast Tax'

by Arushi Kapoor 02 February, 2016

In the early 19th century, Travancore had a barbaric and oppressive law that was highly degrading for its women. The Mulakkaram, or the 'breast tax,' was a tax to be paid by the Dalit women of Travancore per the size of their breasts.

As the law did not allow Dalit women to cover their breasts, the tax was meant to add insult to their injury of being easily identifiable in the most demeaning way.

The regime subjugated the lower castes and ensured they stayed in debt with barbaric laws and taxes on things as trivial as the right to wear jewellery and, for men, the right to grow a moustache.

During these dark times, one woman named Nangeli, and her defiance, brought about a simple, yet revolutionary change that helped abolish the breast tax.

Nangeli was an Ezhava woman from Cherthala, who belonged to a family that could not afford to pay the prescribed taxes.

In a preliminary act of rebellion, Nangeli refused to uncover her breasts whenever it was demanded of her. When the tax collectors of the province came to her home to collect their dues, Nangeli bravely defied them with a final blow. She cut off her breasts and nonchalantly presented it to the collectors in a banana leaf. The tax collectors immediately fled in fear as Nangeli bled to death at her doorstep, and the news spread across the state like wild fire.

In another act of protest, her husband jumped to his death on her funeral pyre, which was also the first recorded instance of a man committing sati instead of a woman.

Following her death, the crown annulled the breast tax in Travancore, as a direct repercussion to her mutilating her own body in defiance. And the land where she lived came to be known as Mulachiparambu (meaning, land of the breasted woman), in her honour.

Several stories of caste oppression and rebellion have faded away from history books. But Nangeli's name will always be etched in the pages of history for bravely sacrificing her life and bringing about radical social change in a world of oppression.

http://www.vagabomb.com/How-One-Womans-Rebellion-Abolished-Keralas-Breast-Tax/

Religion may become extinct in nine nations, study says

A study using census data from nine countries shows that religion there is set for extinction, say researchers.

By Jason Palmer
Science and technology reporter, BBC News, Dallas

The team's mathematical model attempts to account for the interplay between the number of religious respondents and the social motives behind being one.

The result, reported at the American Physical Society meeting in Dallas, US, indicates that religion will all but die out altogether in those countries.

The team took census data stretching back as far as a century from countries in which the census queried religious affiliation: Australia, Austria, Canada, the Czech Republic, Finland, Ireland, the Netherlands, New Zealand and Switzerland.

Their means of analysing the data invokes what is known as nonlinear dynamics - a mathematical approach that has been used to explain a wide range of physical phenomena in which a number of factors play a part.

One of the team, Daniel Abrams of Northwestern University, put forth a similar model in 2003 to put a numerical basis behind the decline of lesser-spoken world languages.

At its heart is the competition between speakers of different languages, and the "utility" of speaking one instead of another.

"The idea is pretty simple," said Richard Wiener of the Research Corporation for Science Advancement, and the University of Arizona.

"It posits that social groups that have more members are going to be more attractive to join, and it posits that social groups have a social status or utility.

"For example in languages, there can be greater utility or status in speaking Spanish instead of [the dying language] Quechuan in Peru, and similarly there's some kind of status or utility in being a member of a religion or not."

Image caption Some of the census data the team used date from the 19th century

Dr Wiener continued: "In a large number of modern secular democracies, there's been a trend that folk are identifying themselves as non-affiliated with religion; in the Netherlands the number was 40%, and the highest we saw was in the Czech Republic, where the number was 60%."

The team then applied their nonlinear dynamics model, adjusting parameters for the relative social and utilitarian merits of membership of the "non-religious" category.

They found, in a study published online, that those parameters were similar across all the countries studied, suggesting that similar behaviour drives the mathematics in all of them.

And in all the countries, the indications were that religion was headed toward extinction.

However, Dr Wiener told the conference that the team was working to update the model with a "network structure" more representative of the one at work in the world.

"Obviously we don't really believe this is the network structure of a modern society, where each person is influenced equally by all the other people in society," he said.

However, he told BBC News that he thought it was "a suggestive result".

"It's interesting that a fairly simple model captures the data, and if those simple ideas are correct, it suggests where this might be going.

"Obviously much more complicated things are going on with any one individual, but maybe a lot of that averages out."

http://www.bbc.com/news/science-environment-12811197

SEND DETAILS OF MEMBERSHIP OF CONFEDERATION

Despite repeated requests we did not get back the receipts of All India Confederation of SC/ST Organizations which were issued to Office-bearers of State/District & Block Units and well-wishers. Please send the following information immediately via e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name of member	M. No.	Distt.	State

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

SEND MOBILE No. OF SUPPORTERS AND WELL-WISHERS

All India Confederation of SC/ST Organizations are requested to send their name, mobile number and district in two categories – Category 'A' is of Confederation leaders and important activists and 'B' of those who are social and supporters of Confederation. Please send e-mail to parisangh1997@gmail.com

Name	Mobile no.	District	State

- Dr. Udit Raj,
National Chairman

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

'70 generations ago, caste stopped people inter-mixing'

India's present diverse population arose from five types of ancient populations that freely mixed and interbred for thousands of years before the rigid caste system, with its principle of prohibition of marriage outside the caste, put an end to this mixing. This ancient history hinted at in various linguistic, archeological and genetic studies has been confirmed by a path-breaking genetic study recently published.

Researchers from the National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG) at Kalyani, West Bengal, analysed DNA samples of 367 unrelated Indians belonging to 20 population groups. These covered castes from different parts of India, and most large tribal populations from central and Northeastern India. Also included were samples from two Andaman & Nicobar tribes.

"Genetic analysis shows mainland India's present population is a result of the intermixing of four main types of ancestral populations - North Indian, South Indian, Austro Asian and Tibeto-Burman," said Partha Majumder, director of NIBMG who led the study. The Andaman & Nicobar tribals have a completely different fifth ancestral origin that originated in Pacific Ocean populations.

The study compared genetic sequences from Indian samples with those from Central Asia, West Asia, China and adjacent regions to trace how humans first arrived in India.

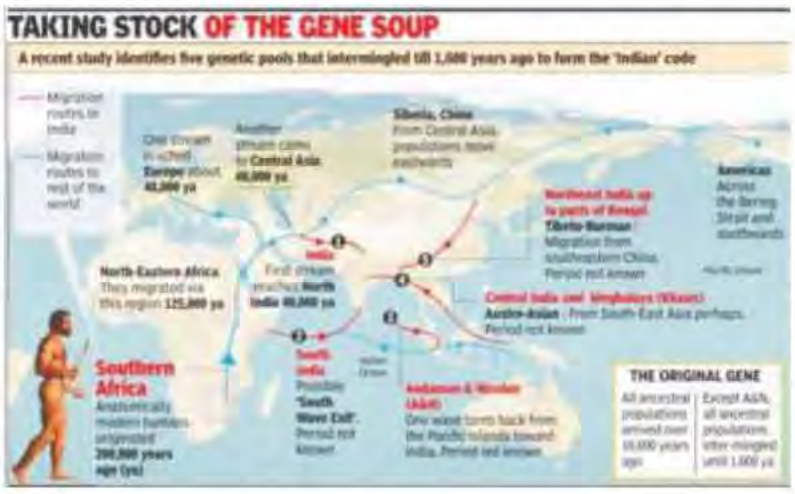

What the study also unearthed was the deep imprint of a significant social cultural process in Indian society . It found that interbreeding between communities `abruptly' ended around 70 generations ago, which translates to about 1,575 years ago, sometime in the 6th century .

"To understand this, we looked at the history of the time. It coincided with the period when the Gupta Empire ruled India," Majumder told TOI. This period had seen the consolidation and supremacy of the caste system, entrenched through the sanction of scriptures as well as enforcing mechanisms of the rulers.

"The genetic revelations corroborate India's history.The genetic mixing was contained by the prescription of a social construct," says Majumder.

David Reich of the Harvard Medical School, known for his extensive genetic analysis from samples of two main ancestral populations of India - North Indians and South Indians told TOI that the new study goes beyond his work by including smaller populations of Autro-Asians, Tibeto-Burmans and Andamanese and Nicobarese.

He cautioned, however, that Majumder and his team's calculation could have erred as they used certain statistical methods software, and also considered 22.5 years as the span of one generation. "Standard citation in genetics literature is 29 years based on studies in many diverse societies around the world. We usually use 29 years and that would give substantially older calendar dates than the authors cite," he told TOI.

Majumder explains his data saying these are estimates. There is scope for correction. "The caste system originated in Vedic times, perhaps 1500 BCE or earlier. It must have slowly spread and got entrenched over centuries. Its impact on genetic material becomes evident around 1600 years ago," he explained.

The new study also found some strange goings on even within the rigidity of endogamy . Ancient North Indian males appeared to continue interbreeding with other population groups but the converse process was not happening, probably due to "elite dominance and patriarchy" the study says.

Genetic analysis also revealed that in many parts interbreeding across caste rigidities continued for some time, as in Bengal and Maharashtra. The establishment of endogamy among tribal populations was less uniform.

The study called "Genomic reconstruction of the history of extant populations of India reveals five distinct ancestral components and a complex structure" has been authored by Analabha Basua, Neeta Sarkar-Roy, and Partha P. Majumder.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/70-generations-ago-caste-stopped-people-Inter-mixing/articleshow/50859632.cms

+++

(Contd. from page 8)

'Dalits face Rohith's ordeals daily...

an apology. The Congress also faced such backlash in the past when Mirchpur caste violence took place in Haryana in 2010.

P.L. Punia, the then chairman of National Commission for the Scheduled Castes, had called Haryana a state of rapists when the state was headed by Bhupinder Singh Hooda.

There were many incidents in the past that went unreported. It's a matter of chance. I know about an incident when five dalits were lynched on suspicion that they had killed a cow in Jhajjar, Haryana.

If untouchability is all-pervasive, as you say, then do you suggest that all positive steps taken in the past six decades have failed in achieving their objectives?

The affirmative actions were unveiled at a time when social "welfarism" was the nature of the state. Business is in control of the state now. The character of the state has been redefined, with the government's role becoming minimal. But even in the past, schemes and funds meant for SC/STs were not implemented or spent.

Then you support the contention of Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan that the reservation policy should be reviewed?

Ms Mahajan spoke in a different context. Had the reservation policy been implemented in true spirit, there would have been no need for quotas/reservations.

Are you suggesting that since there are not many jobs in the public sector, there should be quotas in some form in the private sector?

I would rather favour common schooling system as is the case in Latin America and even the United States, where curriculum, faculty and facilities are same for everyone. In such a scenario, no one would opt for private schools and that will, in the end, help the nation's progress.

It's a misfortune that in India there's no one like Abraham Lincoln, who advocated rights for blacks. Why don't I find a Lincoln in India? We had Mahatma Gandhi and Swami Vivekananda who advocated eradication of caste evils, but not the caste system altogether.

The proposal for quota in promotion for SC/STs is still pending with the Lok Sabha where your party has a majority. When will it be passed?

If this bill is not passed, it may become detrimental to the interests of the SC/STs. Those who are superintendent engineers would be demoted to executive engineers. You can imagine the kind of humiliation they would have to face.

There is a counter-argument that those belonging to the general category too feel humiliated when their juniors become their bosses...

The Indian Institute of Technology and research and development departments are full of upper-caste people. What contributions they have made so far? The judiciary is full of upper caste, but see the kind of justice being delivered.

Reservation in jobs first came in southern states of Travancore (1935), Mysore, Kolhapur (1902), Madras (1921) and they are all much developed than north Indian states where reservation came much later.

But the BJP is feeling much heat on the dalit issue and there are Assembly elections in Assam, West Bengal, Punjab, etc. this year.

In 1996, the I.K. Gujral and H.D. Deve Gowda governments at the Centre had issued five orders. Had the governments completed their terms, these orders would have wiped out reservations from the country.

It was only Atal Behari Vajpayee, who brought three Constitution Amendments (81st, 82nd, and 85th), which negated the consequences of those five orders.

But what did the Congress do in the last 10 years when the bill passed by the Rajya Sabha in 2004 for quota in promotion was pending in the Lok Sabha?

http://www.deccanchronicle.com/opinion/op-ed/310116/sunday-interview-dalits-face-rohith-s-ordeals-daily-plty-we-have-no-lincoln.html

+++

(पृष्ठ 4 का शेष)

सतगुरु रविदास : हमारे महान . . .

अन्न।

छोट बड़ो सब सम बसै,
रविदास रहे प्रसन्न।।''

(मैं ऐसे शासन की स्थापना करना चाहता हूँ जिसमें प्रत्येक मनुष्य को अन्न उपलब्ध हो, कोई भूखा न रहे अर्थात सभी को खाद्य सुरक्षा मिले। मैं ऐसा राज्य का निर्माण करना चाहता हूँ, जिसमें अमीर और गरीब बिना किसी भेदभाव के समान रूप से रह सकें, ऐसे राज्य की स्थापना ही मुझे सुख और खुशी प्रदान कर सकती है। इस पद में इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के शासन की याद ताजा की है और उसे फिर से स्थापित करने की इच्छा जाहिर की है) सतगुरु रविदास ने श्रमण अथवा कमेरी संस्कृति को मजबूत किया है–

''रविदास श्रम कर खाइए,
जौ लौ पार बसाय''

(सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति 'श्रमण संस्कृति' है। उसमें सब अपने–अपने हिस्से का श्रम करते थे। सतगुरु रविदास कामगार समाज में ही पैदा हुए थे। इस समाज की हमेशा से ही श्रम की परम्परा रही है। भीख मांगकर खाने को निम्न समझा जाता रहा है। सतगुरु रविदास कहते हैं जब तक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनी रहती है, तब तक उसको श्रम अर्थात मेहनत करके खाना चाहिए। निठल्ला नहीं बैठना चाहिए और जब वह मेहनत करने की स्थिति में नहीं रहेगा तो उसके परिवार को उसका ध्यान रखना चाहिए)

विश्व फलक के महान चिन्तक कार्ल मार्क्स से भी पहले इन्होंने 'स्वराज' के विचार को प्रतिपादित कर दिया था–

''रविदास मानुश करि बसन कूं,
सुखकर है दुई ठावं।
इक सुख है स्वराज महिं,
दूसर मरघट गांव।।''

(सतगुरु रविदास 'स्वराज' का महत्व स्थापित करते हुए कहते हैं– मनुष्य के सुख और शांतिपूर्वक जीने योग्य दो ही स्थान हैं – एक है 'स्वराज' यानि 'स्वयं का राज', और दूसरा है शमशान घाट अर्थात 'मृत्यु' यानि किसी दूसरे का राज स्वीकार करना मृत्यु समान है) विद्या के महत्व को स्थापित करते हैं–

''सत विद्या को पढ़े,
प्राप्त करे सदा ज्ञान।
रविदास कहे बिन विद्या,
नर को जान अजान।।''

जिस प्रकार बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 'साक्षर' और 'शिक्षित' में भेद करते हैं, उसी प्रकार सतगुरु रविदास कहते हैं– केवल अक्षर ज्ञान प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं है अपितु सही शिक्षा (सत विद्या) प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य समाज कल्याण हेतु प्रयास करता है, वही असली ज्ञानी है अन्यथा उसे अज्ञानी ही समझना चाहिए। उन्होंने धर्म के ढकोसलों को नकारते हैं–

''पांडे हरि विच अंतर डाढा।
मुंड मुंडावें सेवा पूजा भ्रम का बंधन गाढा।।''

अरे पाण्डे (ब्राह्मण) तुझमें और भगवान में बहुत अंतर है। तुमने तो पाखंडवाद फैला दिया है, जिसमें तुम लोगों के सिर मुंडवाते हो, तरह–तरह से पूजा करवाते हो, भ्रम का गहरा जाल फैलाये बैठे हो, जबकि मनुष्य और प्रकृति (भगवान) का संबंध अति सहज है। वे धर्मनिर्पेक्षता की बात करते हुए कहते हैं–

''मुसलमान सों दोस्ती हिन्दुअन सों कर प्रीत।''

(सतगुरु रविदास ने उपदेश दिया है कि अपने पूर्वजों की संस्कृति जो कि सिन्धु घाटी सभ्यता की संस्कृति है उसका पालन करना है। उसके अनुसार धर्म के आधार पर किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए।)

वे जाति के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर ही सम्मान देने की बात करते हैं–

''रविदास बाह्मण मत पूजिए,
जउ होवे गुण हीन।
पुजहिं चरण चांडाल के,
जउ होवे गुन परवीन।।''

(गुणरहित ब्राह्मण को केवल जाति के आधार पर सम्मान देने का निषेध किया गया है, जबकि चांडाल जाति के उस व्यक्ति का भी आदर सत्कार करने का उपदेश दिया है जो गुणों से परिपूर्ण है।)

''रविदास जन्म के कारने
होत न कोऊ नीच।
नर कूं नीच करि डारि है
ओछे करम की कीच।।''

(जन्म के आधार पर कोई ऊँचा या नीचा नहीं होता। मनुष्य को नीचा उसका ओछा व्यवहार बनाता है।)

''जात–जात में जात है
ज्यों केलन में पात।
रविदास न मानुष जुड़ सकें
जों लों जात न जात।।''

(सतगुरु रविदास वर्ण और जाति आधारित विभाजन का पोस्ट–मार्टम करते दिखते हैं– एक जाति के ऊपर या नीचे जातियां ऐसे समाहित की गई है जैसे केले के पेड़ का तना, जिसमें एक के बाद एक परत छुपी रहती है। परन्तु वहां कोई ठोस पदार्थ नहीं होता। इसी प्रकार जाति में भी जाति बना दी गई है, लेकिन उनको भी बांटने का कोई ठोस आधार नहीं है। फिर भी जाति आधारित भेदभाव व्याप्त है जब तक भेदभाव व्याप्त है तब तक मनुष्य एक दुसरे से जुड़ नहीं सकता।) झूठे मंदिर एवं पाखंडी पंडितों को लताड़ते हैं–

''थोथा पंडित थोथी वाणी,
थोथी नाम बिन सबै कहानी।
थोथा मंदिर भोग विलास,
थोथी आन देव की आसा।।''

सतगुरु रविदास ब्राह्मणों के प्रपंचों पर व्यंग्य करते हैं– ब्राह्मण और उनकी वाणी दोनों ही खोखली हैं। जिन कहानियों में नाम (हमारे पूर्वजों के नाम) नहीं वो हमारे लिए खोखली हैं। मंदिरों में भोग–विलास और शोषण होता है और वहां देवता होने संबंधी दावा भी खोखला अर्थात झूठ है। उन्होंने चारों वेदों का खंडन किया है–

''चारिउ वेद किया खंडोति,
जन रविदास करै दण्डोति।''

(सतगुरु रविदास ने चारों वेदों का खंडन किया, हमारे समाज के लिए व्यर्थ घोषित किया। ऐसे वेदों का खंडन करने वाले व्यक्ति को जन–समुदाय दंडवत प्रणाम करता है।)

सतगुरु रविदास अपने अनुयायियों को दलित समाज (तत्कालीन अछूत जातियां) का गौरवशाली इतिहास बताते थे। सन्देश देते थे कि सभी दलित जातियां एक ही परिवार का हिस्सा हैं और ये संगठित रहकर ही मजबूत और सम्मानजनक स्थिति को पा सकती हैं। उन्होंने कहा–

''सतसंगत मिली रहिये माधा
जैसे मधुप मखिरास''

(हे मेरे भाइयों हमेशा अच्छे लोगों के साथ मिल–जुलकर एकता से रहो। एकता में ही बल है। जैसे मधुमक्खियाँ संख्या में अनेक होते हुए भी एक ही छत्ते में मिल–जुल कर रहती हैं। और जब कोई उनमें से किसी एक को भी छेड़ता है तो सारी मधुमक्खियाँ एक शक्तिशाली समूह के रूप में उन पर टूट पड़ती हैं, यही एकता का बल है।)

ब्राह्मण भी दंडवत प्रणाम करते हैं–

''अब बिप्र परधान तिहि करहि डंडउति।
तेरे नाम सरणाइ रविदासु दासा।।''

जब काशी (वाराणसी) के ब्राह्मण वाद–विवाद प्रतियोगिता में सतगुरु रविदास के समक्ष पराजित हो गए, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणों के प्रधान (संभवत रामानंद) सतगुरु रविदास को दंडवत (जमीन में सीधा पेट के बल लेटकर प्रणाम करना) करते हैं। इन्हें पालकी में बैठकर और पालकी को अपने कंधों पर उठा कर पूरी काशी नगरी में शोभा यात्रा करवातें हैं। सतगुरु रविदास कहते हैं कि मैं 'नाम' अर्थात अपने पूर्वजों के नाम की शरण में हूँ इसलिए लोग मेरा सम्मान करते हैं।)

सतगुरु रविदास ने अपने पूर्वजों की परम्पराओं को स्मरण करते हुए ध्यान (मैडिटेशन) करने की विधि बताई है, ध्यान करने का तरीका बताया है जिसमें थोड़े समय के लिए एकांत में बैठकर, आँख बंद करके, अपने पूर्वजों का ध्यान लगाना है, उनको याद करना है, उनके सुख–दुःख और तकलीफों को याद करना है, उनके संघर्ष को याद करना है, उनके ज्ञान पद्धतियों को याद करना है, उनकी परम्पराओं को याद करना है, उनकी वीरताओं को याद करना है, उनके शासन को याद करना है आदिस थोड़े समय के लिए ऐसा प्रतिदिन करना है। यह विधि अपना इतिहास जानने और शारीरिक–मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हिंदी साहित्य के महान हस्ताक्षर सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' अपनी पुस्तक 'अणिमा' में सतगुरु रविदास को चरण छूकर नमस्कार करते हैं–

ज्ञान–गंगा में,
समुज्ज्वल चर्मकार,
चरण छूकर
कर रहा मैं नमस्कार।

सतगुरु रविदास में असीम साहस और बोल्डनैस झलकती है। वे डंके की चोट पर 'कह रविदास चमार', 'कह रविदास खलास चमारा', 'कह रविदास विचार' आदि, स्वाभिमान से लबालब शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। और एक प्रकार से तथाकथित जाति व्यवस्था के पोषकों को करारा जवाब देते हैं। शायद, इसी साहस ने इनको चिंतन के उस स्तर तक पहुंचा दिया जहां से इन्होंने सर्व समाज के लिए आदर्श समाज का मॉडल दिया, वह मॉडल है– 'बेगमपुरा'। सुप्रसिद्ध लेखिका गेल ओम्वेट ने अपनी पुस्तक 'सीकिंग बेगमपुरा' में सतगुरु रविदास को सम्पूर्ण भारतीय इतिहास में प्रथम व्यक्ति माना है जिन्होंने आदर्श भारतीय समाज का 'मॉडल' पेश किया है। यह मॉडल इस प्रकार है–

''बेगमपुरा सहर को नाउ।
दुखु अन्दोहु नहीं तिहि ठाउ।।
ना तसवीस खिराजु न मालु।
खवफु न खता तरसु न जवालु।।
अब मोहि खूब वतन गह पाई।
उहां खैरी सदा मेरे भाई।।
रहाउ सस काइमु दाइमु
सदा पातसाही।
दोम न सोम एक सो आही।।
आबादानु सदा मसहूर।
उहां गनी बसहि मामूर।।
तिउ तिउ सैल करहि जिउ भावै।
महरम महल न को अटकावै।।
कहि रविदास खलास चमारा।
जो हम सहरी सु मीतु हमारा।।''

बेगमपुरा (बेगमपुरा) अर्थात बिना गमों का शहर (पुरा)। वहाँ कोई चिंता (तसवीस) नहीं है, न ही माल पर टैक्स (खिराजु) लगता है। वहाँ खौफ (खवफु), धोखा (खता), लाचारी (तरसु) और अभाव (जवालु) नहीं है। अब मुझे (मोहि) ऐसे देश (वतन) की गहन (गहि) समझ हो गयी है। वहाँ मनुष्य का सदैव ही भला (खैरी) होता है। वहाँ सही विचारों की हुकुमत (पातसाही) है, जो अपने मूल्यों पर सदा स्थिर (काइमु दाइमु) रहती है वहाँ कोई दूसरे (दोम) और तीसरे (सोम) दर्जे का नहीं है सभी एक समान हैं वहाँ कोई धर्म, नस्ल, वर्ण, जाति, लिंग, स्थान, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। हमेशा आजीविका श्रम प्रधान होने के कारण वो स्थान (आबादान) हमेशा प्रसिद्ध रहता है। यह श्रमण परम्परा हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती है और सतगुरु रविदास उसी समानता आधारित राज को प्राप्त करने का आह्वान करते हैं। वहाँ रहने वाले व्यक्ति (गण) कानून (मामूर) के अनुसार आचरण करते हैं। वहाँ पर व्यक्ति जहाँ (तिउ) चाहे उसे वहाँ उसे जाने की स्वतंत्रता है। न ही राजा के कर्मचारी (महरम) उसे रोकते हैं और न ही महल की ऐसी व्यवस्था है कि किसी की आजादी का हनन करें। बेखौफ (खलास) चमार रविदास कहता है कि जो उस नगर (बेगमपुरा) के विचार के समर्थक हैं वही मेरे साथी हैं, मित्र हैं।

विश्व प्रसिद्ध लेखिका गेल ओम्वेट के अनुसार– ''यूरोप के टॉमस मूर ने आदर्श समाज की परिकल्पना 'यूटोपिया' का विचार सन् 1516 ई. में दिया, लेकिन टॉमस मूर से भी कहीं पहले, रविदास ने आदर्श समाज की परिकल्पना 'बेगमपुरा' के रूप में विश्व के सामने रख दी थी।''

इनके 'बेगमपुरा' पद में जो विचार निहित हैं वही विचार 'भारतीय संविधान' में निहित हैं, वही विचार संयुक्त राष्ट्र संघ के 'मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा–पत्र' के आर्टिकल–1 में भी निहित हैं। इनके विचारों का लक्ष्य विश्व कल्याण हेतु विश्वबंधुत्व की भावना का प्रसार करना है।

आसाड़ सक्रांति, विक्रम संवत् 1584 को इनका शरीरांत हो गया।

लेकिन इनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। इनका मार्गदर्शन समाज, देश और समूचे विश्व के लिए अतिमहत्वपूर्ण है। अगर इनके विचारों का सही रूप में पालन किया जाए तो विश्व फलक पर भी एक समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज का निर्माण करना मुश्किल नहीं होगा। आज जिस प्रकार का सामाजिक वातावरण बना हुआ है, उसमें संतरविदास की वाणियों की जरूरत महसूस की जा रही है।

– डॉ0 मनोज कुमार

सतगुरु रविदास : हमारे महान क्रांतिकारी पूर्वज

विश्व की एक महान शख्सियत हैं- सतगुरु रविदास। इनका का जन्म माघ पूर्णिमा, विक्रम संवत् 1433 में सीरगो- वर्धनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। आज इनके जन्म स्थान सीरगोवर्धनपुर पर सात मंजिला भव्य धर्मस्थान निर्मित किया गया है और उसके अनेक गुम्बद स्वर्णमंडित हैं। इस धर्मस्थान का नाम रखा गया है- सतगुरु रविदास जन्म स्थान। इसी स्थान पर इनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष बड़े धूम-धाम और हर्षोउल्लास से मनाया जाता है। पूरे देश और विदेशों (अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, सऊदी अरब, दुबई, पुर्तगाल, ग्रीस, आफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, स्कॉटलैंड, नोर्वे, इटली आदि) से लाखों लोग इनके जन्मदिवस पर पंहुचते हैं। इनके परिवार का परिचय इस प्रकार हैं - पिता जी- संतोख दास, माता जी- कलसी देवी, दादा जी- कालू राम, दादी जी- लखपति, पत्नी- लोना देवी, पुत्र- विजय दास।

उस काल में अधिकतर चीजें चमड़े की ही बनती थी और जो चमड़े का व्यापार करते थे, उनकी आदमनी बहुत अच्छी होती थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। इनके पिता संतोख दास जी एक प्रतिष्ठित चर्मकार थे। उनके यहां चमड़े का अच्छा कारोबार था। कारखाने में खालों की सफाई और रंगाई, जूते, जीन, लगाम, ढोल, मशक और पुर इत्यादि भी तैयार होते थे। बड़ा कारखाना था, जिसमें बहुत से कारीगर काम करते थे। इनका व्यापार इरान, इराक, सऊदी अरब आदि देशों तक होता था। कारोबार से बड़ी अच्छी आमदनी होती थी।

संतोख दास जी दलित समाज की समस्यायों और जरूरतों से भली-भांति परिचित थे। इसलिए समय-समय पर समाज के लोगों का आर्थिक-सामाजिक सहयोग भी करते रहते थे। उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी, जब भी दलित समाज में कोई समस्या आती तो संतोख दास जी जाकर उनका फैसला तुरंत करवा देते थे। वैसे भी पुराने समय से ही 'चमारों की पंचायत का न्याय' अपनी निरपेक्षता, व्यवहारिकता और तुरंत समाधान के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराजा अकबर ने भी बीरबल से पूछा था कि "किस पंचायत का न्याय आपकी दृष्टि में सबसे अधिक उचित और तर्कसंगत होता है?" बीरबल ने उत्तर दिया- "चमारों की पंचायत का"।

सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी होने और भरा-पूरा परिवार होने के कारण सतगुरु रविदास का बचपन बहुत ही अच्छे और हंसी-खुशी के वातावरण में बीता। उनके ओजमय व्यक्तित्व, मिलनसार और खुशनुमा व्यवहार से सभी खुश रहते थे। किशोर अवस्था से ही सतगुरु रविदास जब भी गरीब साधुओं को नंगे पैर देखते तो उन्हें जूते मुफ्त में ही दान कर दिया करते थे ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। उनके साथ बैठकर घन्टों उनसे विभिन्न विषयों पर लम्बी चर्चाएं करते थे। इसी प्रकार इनका अधिकतर समय समाज सेवा और साधुजनों से विचार-विमर्श में ही बीत जाता था। परिवार के कारोबार में इनका मन नहीं लगता था। इनके पिता चाहते थे कि उनका पुत्र कारोबार को विकसित करे और परिवार की समृद्धि में ही मन और समय लगाये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए इनके पिता ने चंबा (हिमाचल प्रदेश) के एक भले परिवार की बेटी लोना देवी से इनका विवाह कर दिया तथा अपने पुत्र को अलग से अपनी गृहस्थी बसाने और चलाने का आदेश दिया। घर से अलग होकर अपनी गृहस्थी चलाने के लिये इन्होंने स्वयं मोची का कार्य भी किया। परन्तु, इन सब के बावजूद भी सतगुरु रविदास अधिकतर समय चिन्तन-मनन एवं विचार गोष्ठियों में लगाया करते थे। धीरे-धीरे इनके ज्ञान की आभा समाज में चारों तरफ फैलने लगी। समाज में इनकी पहचान बनने लगी, इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होने लगे। अपने तेजस्वी पुत्र का सामाजिक मुद्दों पर गहन चिंतन-मनन और समाज में बढ़ते इनके प्रभाव से इनके पिता बहुत प्रभावित हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने सतगुरु रविदास को फिर से अपने घर-परिवार में शामिल कर लिया और इनके स्वतंत्र विचारों का सम्मान करते हुए सभी प्रकार का सहयोग देना भी प्रारम्भ कर दिया। घर पर हंसी-खुशी का माहौल बन गया।

सतगुरु रविदास और लोना देवी एक आदर्श दम्पति के तौर पर जाने जाते थे। उनका परस्पर व्यवहार प्रेम पूर्ण और सम्माननजनक था। सतगुरु रविदास के सामाजिक कार्य तो जग में प्रसिद्ध थे ही, उनकी पत्नी लोना देवी भी एक अच्छी औषधि ज्ञाता थी। लोना देवी खुद गॉव-गॉव जाकर गरीब असहाय लोगों का इलाज करती, साफ-सफाई से रहने को कहती, मस्तिष्क और शरीर को सक्रिय बनाये रखने की सलाह देती थी। इस प्रकार दोनों ही पति-पत्नी सामाजिक कार्यों में लगे रहते दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग और सम्मान करते थे। दोनों एक आदर्श दम्पति के तौर पर प्रसिद्ध थे।

अछूत समाज में परम्परागत रूप से चली आ रही

ज्ञान-पद्धति और विभिन्न विद्वानों के साथ विचार-गोष्ठियों, चर्चाओं और वाद-संवाद के माध्यम से इन्होंने स्वयं बहुत ज्ञान अर्जित किया। अनेक धर्मों का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक भाषाएँ सीखीं जैसे- अरबी, फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हिंदी आदि। इन्होंने अपने विचारों को वाणी दी, जो कि सारगर्भित, अनूठी और प्रभावशाली है। इनकी वाणी सिख समुदाय के धार्मिक ग्रन्थ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' में विभिन्न रागों में दर्ज है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि इन्हें संगीत विद्या का भी बहुत गहरा ज्ञान था। वर्तमान समय में इनकी वाणी 27 रागों में उपलब्ध होती है जो कि इनके संगीतज्ञ होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी 'श्री गुरु ग्रन्थ साहिब' में 40 से भी अधिक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग 'ग्रन्थ' में अन्य किसी महापुरुष द्वारा प्रयोग नहीं किया गया है। यह प्रमाणित करता है कि इनका शब्द भण्डार कितना पृथक एवं विशाल रहा होगा।

इन्होंने एशिया के लगभग सभी देशों के साथ-साथ सुदूर इरान, इराक, सऊदी अरब आदि देशों की यात्राएं की और अपने तार्किक और चिंतनपरक विचारों से लोगों को प्रभावित किया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने जिन साधु-महापुरुषों की टोली से मिल वार्तालाप कर आध्यात्मिक संतुष्टि का अनुभव किया, वह टोली सतगुरु रविदास की अगुवाई में चुहड़ काने (अब पाकिस्तान में) में विश्राम कर रही थी। गुरु नानक देव ने महापुरुषों की इस टोली के साथ ही 'सच्चा सौदा' किया था। सतगुरु रविदास और गुरु नानक देव के मध्य हुआ यह 'सच्चा सौदा' भारतीय इतिहास में प्रमुख अध्याय के रूप में प्रसिद्ध है। इनके समय के अनेक राजा-रानियों और विशाल जन-समुदाय ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया था। जैसे- चितौड़ की प्रसिद्ध राजपूत महारानी मीराबाई, राजा बेन सिंह, महाराणा सांगा, महारानी झाला बाई, राजा हरदेव सिंह, राणा वीर सिंह बघेल, बीबी भानमती, महाराणा कुम्भा, राजा रतन सिंह, सिकंदर लोधी, अलावादी बादशाह, बिजली खान आदि लगभग 52 राजा-रानियों ने सतगुरू रविदास महाराज जी को अपना राज गुरु माना, जिससे उनके राज-पाठ बड़े ही सुचारू रूप से चले। अनेक विभूतियों ने भी इनकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है, इनमें से कुछ हैं-कबीरदास, मीराबाई, झालाबाई, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, भाई गुरदास, नामदेव, सधना, सेन, पीपा, धन्ना, बाबा फरीद, एकनाथ, पिंधु साहिब, गुलाल, दरबारी दास, रज्जब, ध्रुवदास, हरी दास, सूरदास, दयाबाई, नारायण, रज्जब अली, नाभादास, प्रियदास, बालक राम, जयगोपाल, चरणदास, दादू दयाल, गरीबदास, दर्शनदास, सेवादास, तुकाराम, पलटूदास, कमाल, अनंतदास, कल्याणदास, सुन्दरदास, रूपराज आदि।

भारत देश के जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, मुख्यमंत्री आदि हुए हैं, लगभग सभी ने सतगुरु रविदास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और आज तो लाखों-करोड़ों लोग इनके विचारों को आदर्श मानते हैं, इनको अपना आराध्य भी मानते हैं, जिसके उदाहरण देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े स्तर पर दिखाई पड़ते हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) में सन् 2011 में दशकीय जनगणना हुई जिसमें 11,058 लोगों ने आधिकारिक रूप से 'रविदासिया धर्म' अपनाया।

सतगुरु रविदास ने राजपूत रानी मीराबाई को अपनी शिष्या स्वीकार किया। वह भी उस समय जब कोई भी स्त्री को अपना शिष्य नहीं बनाता था। यह नारी जाति के सम्मान में एक महत्वपूर्ण कदम था। जब मीराबाई के पति का देहांत हो गया, तो उस वक्त राजपूताने में प्रचलित सतीप्रथा के अनुसार पत्नी को अपने पति के साथ ही चिता में दहन होना था। लेकिन अपने सतगुरु के मार्गदर्शन पर मीराबाई और उनके परिवार ने इस क्रूर प्रथा को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार सतगुरु रविदास ने सतीप्रथा को समाप्त करने की परम्परा नींव डाली। मीराबाई ने अपने सतगुरु की कृतज्ञता में चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) के किले में स्थित कुम्भा श्याम मंदिर (मीरा मंदिर) के प्रांगण में सतगुरु रविदास की चरण पादुकाएं भी बनवाई हैं।

सतगुरु रविदास ने ही पंजाबी भाषा की लिपि 'गुरुमुखी लिपि' का निर्माण किया। लाहौर (अब पाकिस्तान में) की अदालत में यह मुकदमा भी चला कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि का निर्माण किसने किया? इस मुकदमें का फैसला 11 मार्च, 1932 में आया जिसमें यह माना गया कि 'गुरुमुखी लिपि' का निर्माण सतगुरु रविदास ने ही किया है। एक नई भाषा का निर्माण कर इन्होंने विश्व सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी वाणी विविध आयाम लिए हुए है। समाज के अनेक पहलुओं को इन्होंने उजागर किया है, कुछ उदाहरणों को देखा जा सकता है।

सतगुरु रविदास इतिहास में सबसे पहले पराधीनता (दूसरे की गुलामी) को पाप कहने वाले प्रथम व्यक्ति भी हैं -

पराधीनता पाप है,
जान लेहु रे मीत।
रविदास दास पराधीन सों,
कोन करे है प्रीत।।"

(मेरे मित्रों जान लो कि पराधीनता (गुलामी) पाप है और गुलाम व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता। खाद्य सुरक्षा की बात भी भारतीय इतिहास में सबसे पहले इन्होंने ही उठाई-

ऐसा चाहूँ राज मैं,
जहां मिलै सबन को

(शेष पृष्ठ 5 पर)

केंद्रीय विश्वविद्यालय : एससी, एसटी ओबीसी के 58% शिक्षक पद खाली

बीएचयू ने सामान्य वर्ग में स्वीकृत पद से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की

अमित कुमार निरंजन नई दिल्ली।

देश के 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी/एसटी और ओबीसी कोटे के शिक्षकों के 58 फीसदी पद खाली हैं। इन वर्गों के लिए स्वीकृत 4763 पद में से सिर्फ 1977 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर की नियुक्तियां हुई हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीएचयू और एचएनबी गढ़वाल ने स्वीकृत पदों से ज्यादा नियुक्तियां सामान्य वर्ग में कर ली थी। आंकड़े एक साल पुराने हैं लेकिन वर्तमान में भी इनकी प्रासंगिकता है क्योंकि हाल ही में हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद आरक्षण का मुद्दा गर्माया हुआ है।

आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 2015 में आरटीआई के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से केंद्रीय विवि में एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के शिक्षकों का ब्योरा मांगा था। आरटीआई (2015) के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 6107 असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद खाली हैं। इनमें 1135 एससी, 610 एसटी और 1041 ओबीसी कोटे के पद हैं। जबकि शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 16339 हैं। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि प्रोफेसर पद के लिए एससी कोटे के लिए स्वीकृत 276 पदों में सिर्फ 38 पद और एसटी कोटे के लिए स्वीकृत 124 में से सिर्फ 11 पद पर नियुक्तियां हुई थीं। जबकि शारीरिक विकलांग कोटे से 232 पद खाली हैं।

- 49 प्रोफेसर के पद पर एससी–एसटी वर्ग के हैं
- 1041 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद ओबीसी कोटे के खाली
- 3089 शिक्षकों के पद सामान्य वर्ग से खाली हैं,
- 16339 शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं

इस संबंध में यूजीसी ने कई बार विवि प्रशासन को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया कि आरक्षित पदों को भरने की पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है।

आरटीआई से खुलासा

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें खाली शिक्षकों (सभी वर्ग) के सबसे ज्यादा 1667 पद उत्तर प्रदेश के चार केंद्रीय विवि में खाली हैं। दिल्ली प्रदेश के तीन विवि में 1405, उत्तराखंड के एक विवि में 165, जम्मू व कश्मीर के दो विवि में 172, हरियाणा के एक विवि में 145, हिमाचल के एक विवि में 121, पंजाब के एक विवि में 111 असि. प्रोफे., असो. प्रोफे., प्रोफेसर के पद खाली थे।

साभारः अमर उजाला,
नई दिल्ली (11 फरवरी 2016)

✦✦✦

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब इंडस्ट्री की जमीन भी दलितों के लिए आरक्षित

महाराष्ट्र में उद्योग शुरू करने के लिए दलितों को विशेष आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण राज्य सरकार की औद्योगिक जमीन पर दिया जा रहा है। राज्य कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मंझोले उपक्रम चलाने वाले दलित कारोबारी ही इस आरक्षण के हक़दार होंगे।

महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) की कुल जमीन में से 20 फीसदी जमीन इन उद्यमियों के लिए आरक्षित होगी। महाराष्ट्र सरकार के पास इस समय करीब 57 हजार हेक्टेयर औद्योगिक जमीन है। जिसमें से 11 हजार 400 हेक्टेयर पर यह आरक्षण लागू होगा। इस जमीन को दलित उद्यमियों को तय सरकारी दामों से 30 फीसदी कम कीमत पर दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने सरकारी फैसले पर NDTV इंडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार सभी को एक साथ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है। इसके तहत MIDC की जमीन पर आरक्षण दिया गया है। जिसका लाभ लेने वाले कारोबारी अगर सफल होंगे तभी मेक इन महाराष्ट्र का उद्देश्य सफल होगा।

उद्योगों के सर्वे में सामने आया है कि अमूमन 15 फीसदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम दलित उद्यमी बने हुए हैं। जबकि शिक्षा और सरकारी नौकरी में दलितों के लिए महाराष्ट्र में 13 फीसदी आरक्षण लागू है।

दलितों में उद्यमिता के लिए भरसक कोशिश करते संगठन DICCI के अध्यक्ष मिलिंद काम्बले ने राज्य कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। उन्हें इस काम के लिए पद्मश्री सम्मान घोषित हुआ है। NDTV इंडिया से बात करते हुए काम्बले ने कहा कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र में भी सरकारी औद्योगिक जमीन पर दलित उद्यमियों के लिए आरक्षण लागू हो रहा है। सरकारी नौकरी के कम होते अवसर देखते हुए कारोबार करने से ही दलितों में बदलाव आएगा। सरकार की पहल इस तरफ़ सकारात्मक है।

http://khabar.ndtv.com/news/india/maharashtra-govt-approves-cast-base-reservation-on-industrial-land-1275228

✦✦✦

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए
एक वर्ष : 150 रुपए

दलितों के साथ हर घंटे 5 अपराध

संदीप राय
बीबीसी हिंदी डॉट कॉम

हैदराबाद यूनिवर्सिटी के शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद दलितों के साथ भेदभाव पर एक तीखी बहस छिड़ गई है।

मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे दलित बनाम गैर दलित मामला मानने से इंकार किया है। लेकिन दलित और अन्य सामाजिक संगठन इसे दलितों के खिलाफ़ भेदभाव का ही नतीजा बता रहे हैं। वे हैदराबाद विश्वविद्यालय के कुलपति समेत मामले में शामिल रहे दूसरे लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हैदराबाद विश्वविद्यालय जाकर दलित छात्रों से मुलाक़ात की। उन्होंने कुलपति और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पर भेदभाव के आरोप भी लगाए। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में दलितों के खिलाफ़ उत्पीड़न के मामलों की कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक साल 2014 में दलितों के खिलाफ़ 47064 अपराध हुए।

यानी औसतन हर घंटे दलितों के खिलाफ़ पांच से ज़्यादा (5.3) के साथ अपराध हुए। अपराधों की गंभीरता को देखें तो इस दौरान हर दिन दो दलितों की हत्या हुई और हर दिन औसतन छह दलित महिलाएं (6.17) बलात्कार की शिकार हुईं। अगर यूपीए–एक और यूपीए–दो के दस सालों के शासन के दौरान दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर नज़र दौड़ाएं, तो कांग्रेस को खुद पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2004 से 2013 के दरम्यान दस सालों में 6,490 दलितों की हत्याएं हुईं और 14,253 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुए।

ब्यूरो के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन में दलितों के खिलाफ़ उत्पीड़न के दर्ज होने वाले अपराधों में लगातार बढ़ोतरी का एक समान ढर्रा दिखता है। साल 2014 में दलितों के खिलाफ़ होने वाले अपराधों में इसके पिछले साल के मुक़ाबले 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे एक साल पहले 2013 में दलितों के खिलाफ़ अत्याचार के मामलों में 2012 के मुक़ाबले 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अपराध की दर भी बढ़ी है, 2013 में यह 19.6 थी तो 2014 में यह 23.4 तक पहुंच गई।

दलित हत्याओं के मामलों में भी लगातार इजाफ़ा दिखता है। नब्बे के दशक में जहां ये आंकड़ा पांच सौ के आस पास बना रहा, वहीं पिछले दशक में ये छह सौ के पार पहुंच गया और 2014 में तो यह 744 तक पहुंच गया।

एनसीआरबी ने साल 2015 के आंकड़े अभी जारी नहीं किए हैं और इस साल के जून तक इन आंकड़ों के आने की उम्मीद है।

रोहित वेमुला की आत्महत्या ने शैक्षणिक संस्थानों में दलित छात्रों के साथ अलग बर्ताव को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

हालांकि शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाले भेदभाव को लेकर कोई मान्य और व्यापक अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन समय–समय पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। इस घटना से पहले आईआईटी मद्रास में आंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाने की घटना ने इस ओर सबका ध्यान खींचा था। कुछ साल पहले देश के अग्रणी मेडिकल संस्थानों में से एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी दलित छात्रों ने भेदभाव की शिकायत की थी। देश के आईआईटी जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती को लेकर दलित और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव को लेकर आरोप–प्रत्यारोप लगते रहे हैं।

साल 2010 में दिल्ली के वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज में सामूहिक रूप से 35 दलित छात्रों के फेल होने का मामला जब तूल पकड़ा तो अनुसूचित जाति आयोग ने एक जांच कमेटी बनाई, जिसने भेदभाव के आरोपों को सही पाया था।

यह मामला सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों तक ही सीमित नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में लागू दोपहर के भोजन की योजना में भी दलित रसोइये और दलित बच्चों के साथ भेदभाव की ख़बरें सुर्खियां बनती रही हैं। संविधान के अनुच्छेद 15, 38, 39 और 46 में जाति, धर्म, नस्ल, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न किए जाने और एससी–एसटी के कमज़ोर तबकों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की बात कही गई है। इसके लिए क़ानूनी तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ़ सिविल राइट्स एक्ट (1955) और एसएस/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) ऐक्ट 1989 लागू है।

एस.सी./एस.टी. ऐक्ट के तहत आईपीसी के मुक़ाबले कड़ी सज़ाओं का प्रावधान है। इन क़ानूनों के तहत आने वाले मामलों की तेज़ सुनवाई के लिए कई राज्यों में विशेष अदालतें भी गठित की गई हैं। लेकिन लगता है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में कमी की बजाय बढ़ोतरी ही हो रही है। (बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं)

http://www.bbc.com/hindi/india/2016/01/160122_dalit_atrocities_pm

✦✦✦